13.46 hrs.

BIHAR APPROPRIATION BILL,* 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1969-70.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, rule 340 of the Rules of Procedure says:

> "At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned."

Now a motion has been moved by the Minister about the Bihar Appropriation Bill. My motion is that the debate on this motion be adjourned. I will now give my reasons for it. A much more important thing is happening in the country today, and that is the token strike by the PTI employees. That strike has taken place because of the arrogant attitude of the management of the PTI in not conceding the demand for bonus. You may rule out my motion. But before rejecting my motion, kindly hear me for one minute. I want the Minister to make a statement on this token strike.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not relevant to the question now before the House. Therefore, I cannot allow it.

SHRI UMANATH (Pudukkottai): But a motion has been moved. I support that motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will rule it out under rule 341.

SHRI S. KUNDU (Balasore): Let the Minister make a statement.

SHRI S. M. BANERJEE: Under rule 341 you have either to put the motion to the vote of the House or declare it out of order. The rule says "If the Speaker is of opinion that a motion for the adjournment of a debate is an abuse of the rules.. ." I am not abusing the rule.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anyhow, I am not convinced. Kindly cooperate with me.

SHRI S. KUNDU: Whatever you may decide about the motion, the point is that they are inter-connected.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I do not accept it. They are not inter-connected.

SHRI S. KUNDU: While disposing of this motion, you can ask the Government to make a statement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, it is not possible. When I have not allowed him to move it, how can I ask the government to make a statement.

SHRI KAMESHWAR SINGH (Khagaria): The farmers will suffer.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him raise it at the proper time. Now the question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1969-70."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI: I introduce† the Bill.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : प्वाइंट आफ आर्डर..........

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly listen to me for a minute.

श्री शिव चन्द्र झा : मैं इसको अपोज करना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Unless you listen to the Chair, how can you expect the Chair to hear you? I have already put the question to the vote of the House. Now it is too late to raise any point.

श्री कामेश्वर सिंह : इस पर तो बहस होनी चाहिए : .... (व्यवधान) ......

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him resume his seat. Now the Minister.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 22-12-69.

†Introduced with the recommendation of the President.

SHRI P. C. SETHI: I beg to move:*

"That the bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration."

श्री लखनलाल कपूर (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जब डिस्कशन चल रहा था तब मैं बाहर था इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समय मुझे भी दिया जाये। मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Kindly listen to me. Last Saturday we have had a full discussion on the Demands for Grants of Bihar and more than the allotted time was taken. Now, this is more a formality. If hon. Members again raise all those points, I am afraid we are not strictly following the convention. So, I would request hon. Members to be brief.

THE MINISTER OF PALIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): May I request you, Sir, to put some time-limit?

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is right. If I allow one hon. Member, I have to allow others also. I have to be impartial. I cannot discriminate between Members. Since we have already spent so much time on this, let us be as brief as possible. Therefore, let hon. Members not take more than two minutes.

श्री कामेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंशी रहीमपुर में जो कटाव हो रहा है उसके निर्माण कार्य में 15 प्रतिशत बिहार सरकार का हिस्सा होना चाहिए और वह है भी लेकिन बिहार सरकार उस खर्चे को करने से पीछे हट रही है। कहा जाता है कि सारा खर्चा रेल मंत्रालय और ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री करे। मुझे मिनिस्टर साहब से कहना है कि इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि 15 प्रतिशत क्यों नहीं खर्च करेंगे। जब यह लाखों लोगों का सवाल है तो वह खर्च किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि खगरिया बेगूसराय में सरकारी और प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं लेकिन अभी तक वहां पर बिजली की लाइन नहीं गई है। यह बड़े अफसोस की बात है। इसके अलावा एक सरकारी स्कीम थी कि जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां पर स्टेट ट्यूबवेल लगाये जायेंगे ताकि किसान बाढ़ आने से पहले अपनी फसलें काट लें। परन्तु उस स्कीम में भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। पता नहीं सारा पैसा कहां चला जाता है? इसी प्रकार से 22 मील लम्बे पैकांत इम्बैंकमेन्ट का सवाल है। रुपया होता है लेकिन पता नहीं वह कहां चला जाता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि बरसात के पहले-पहले सारे ट्यूबवेल लग जायं और बिजली की लाइन पहुंच जाये। पैकांत बांध में, जहां-जहां बाढ़ आई थी, वहां पर काफी डैमेज हुआ है। इसी तरह से गंगा, गंडक, कोसी के इम्बैंकमेन्ट्स को जून के पहले ठीक करवा दें—सारे रिपेयर वर्क्स हो जायं। गंडक में जो कटाव हो रहा है, मोहनपुर, टेकनापुरा, छितौना और बागड़ में, वहां पर कही भी रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। पैसा होते हुए भी काम शुरू नहीं होता है। वह आपसे पैसा भी पास करवा लेंगे लेकिन काम शुरू करेंगे जुलाई के महीने में और उस वक्त जो मिट्टी और बांस वगैरह डालेंगे वह सब पानी में बह जायेगा। इस तरह से सारा रुपया पानी में बहा दिया जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि खगरिया, मंशी में जो खर्चा होगा उसका 15 प्रतिशत आप रेलवे और ट्रान्सपोर्ट

*Moved with the recommendation of the President.

मिनिस्ट्री को देंगे या नहीं, उसका यहां पर साफ जवाब दें ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिहार की अभी स्थिति है उस को देखते हुए मैं अर्ज करूंगा कि अगर वहां तुरन्त लोकप्रिय सरकार नहीं बनती है तो वहां विधान सभा भंग कर के नये चुनाव करा लें । बिहार गवर्नरी शासन से मुक्ति चाहता है । उस को बिहार लम्बी अवधि तक नहीं ले जाना चाहता है । जहां तक इन स्थितियों का सवाल है मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में कागज की कमी का सवाल आया है । लेकिन बिहार में दो कागज मिलें हैं अशोक पेपर मिल और ठाकर पेपर मिल जिन में से साढ़े सात करोड़ रु० अशोक पेपर मिल पर लगे हुए हैं । चार करोड़ रुपये की विदेशी मशीन वहां बेकार पड़ी हैं । सरकार उस को अपने हाथ में ले और उस का ठीक से संचालन कर के उस को रिहैबिलिटेट करे । सब चीजें एग्जामिन हो गई हैं । इस को ले कर वह शीघ्र से शीघ्र चालू करे ।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : और चौपट करे ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं आशा करता हूं कि चौपट करने वालों को हम लोग पहले चौपट कर के बदल देंगे । जो चीज देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति है वह हम चाहते हैं कि चालू हो ।

वैसे ही देश में एक मात्र प्रोजेक्ट वेस्टर्न कोसी प्रोजेक्ट है जिस का तीन बार उद्घाटन हो चुका है । पहले प्रधान मंत्री ने उद्घाटन किया, फिर दूसरे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस का उद्घाटन किया, और मुख्य मंत्री ने किया । तीन बार उद्घाटन होने के बाद भी वह आज तक शुरू नहीं हुई । ऐसी कोई दूसरी योजना देश में नहीं है । इस की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

वैसे ही मैं डा० वी० के० आर० वी० राव को बतलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन ने दो साल पहले सिफारिश की मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये, लेकिन अभी तक बिहार का गवर्नरी शासन उस पर बैठा रहा । उस ने अब तक कोई रिपोर्ट तक नहीं दी है । इन मामलों पर मंत्री महोदय राय लें । अभी पटना विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में सवाल उठाया गया । वहां विद्यार्थियों की हड़ताल हुई । आर० के० कालेज मधुबनी और मिल्लत कालेज दरभंगा में चार-चार महीने से लोगों को मुशाहरा नहीं मिला है । इन सब बातों को सरकार देखे । या तो केन्द्रीय सरकार वहां की स्थिति में सुधार करे या फिर उस को अपने मातहत ले ले । आज यह मांग उठी है । मेरा आग्रह है कि वह इस ओर जल्दी ध्यान दे जिस में वहां पर कोई आन्दोलन न खड़ा हो जाये ।

आखिरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जमशेदपुर की हड़ताल की बात यहां कई बार उठ चुकी है । आज उस के 35 दिन हो चुके हैं । श्रम मंत्री महोदय ने सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है । मेरा आग्रह है कि यह मंत्री महोदय के बूते की बात नहीं है कि इस को हल करें । टाटा सरकार भारत सरकार से ऊपर है । ऐसी स्थिति में इस चीज को आश्वासन समिति में भेजा जाय । सदन में आश्वासन दिया जा चुका है कि जो विक्टिमाइजेशन हो चुका है वह दुरुस्त होगा । अभी तक 150 आदमी मुअत्तल हैं, उन की हड़ताल चल रही है, पता नहीं वह कौन सा रुख लें । इस लिये इस को ऐश्योरेंस कमेटी को भेजा जाय और उस ऐश्योरेंस को तुरन्त लागू किया जाय ।

श्री लखनलाल कपूर (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार में राष्ट्रपति शासनकाल में ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसा शासन नहीं है जिस मे जन-कल्याण का कोई कार्य चल रहा हो। आप जानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा

[श्री लखनलाल कपूर]

हुआ राज्य है और वहां की जनता की जो आर्थिक स्थिति है वह सब से गिरी हुई है। मैं पूर्णिया और सहरसा जिलों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह इलाका खासकर जूट और धान का इलाका है। इस के बारे में बार-बार सदन का ध्यान दिलाया जा चुका है कि जूट का उत्पादन करने वाले जो लोग हैं उन की उन्नति या उन की रक्षा के लिये कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं है जिस से उन का जो आर्थिक शोषण हो रहा है मिल मालिकों द्वारा, उस को रोका जा सके। यह इतने परिश्रम का काम है फिर भी न तो उन के लिये कोई अच्छा बीज दिया जाता है समय पर, न कोई रीटिंग की व्यवस्था है। जूट के लिये पानी की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, न ही उस इलाके में सड़कें हैं जिन के द्वारा वह जूट को गाड़ियों में लाद कर बाजार में ले जा सकें। उन को पीने के लायक पानी भी नहीं मिलता। वहां पर कुएं और ट्यूबवेल भी नहीं हो पाये हैं। नार्थ बिहार में जब ऐसी विशेष अवस्था है तब या तो आप जूट का उत्पादन जो हो रहा है उस को बन्द करें या फिर जूट उत्पादकों और मिल मालिकों द्वारा जो हजारों परिवारों का शोषण हो रहा है, जिन की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उस को बन्द कीजिये और उन को मिनिमम वेज दिलवाइये। जो मिनिमम वेज आप ने तय किया है 40 रु० की वह कलकत्ते पहुंच कर कलकत्ते की मार्केट में मिलती है। वह किसानों को नहीं मिलती। किसान लोग जो घरों में अपने जूट को बेचते हैं उन को 25 से 30 रु० तक मिलता है। खर्च वगैरह सब मिला कर उन को 35 रु० पड़ जाता है। इस को पूरा करने के लिये कर्ज लेना पड़ता है। चूंकि वह बराबर कर्ज लेते जा रहे हैं, इस लिये उन का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जूट एक्सट्रैक्ट करने का, रेशम निकालने का तौर तरीका है वह बहुत गन्दा और मेहनत वाला है। इस के लिये कोई साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिये जिस से जूट निकालने का कोई सहल तरीका निकल आये और लोगों को यह काम आसान मालूम हो।

14 hrs.

दूसरी बात यह है कि पूर्णिया जिले में बड़ी भयंकर बाढ़ आई और उस में सारी फसल बह गई, लोग भूखों मरने लगे। उन को कोई रिलीफ की चीज नहीं दी गई, जिस के कारण वहां सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन चलाया और सत्याग्रह किया। जो परती जमीन पड़ी हुई है उस के बटवारे के लिये अभी कुछ नहीं किया गया है। बाइस सालों से उस जमीन को भूमिहीनों को नहीं बांटा गया है। इस लिये सत्याग्रह हो रहा था। लोगों पर लाठियां बरसाई गईं और उन को जेलों में बन्द किया जा रहा है। इसी तरह से टाटा नगर में स्ट्राइक हुआ। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती है और मैनेजमेंट नहीं मानता है, तो सरकार उन कारखानों को अपने हाथ में ले कर वहां का स्ट्राइक तुड़वाये और लोगों को सहूलियत प्रदान करवाये।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भोगेन्द्र झा ने अभी-अभी बिहार की कुछ मिलों की चर्चा की। मैं उन का समर्थन करते हुए कहूंगा कि अशोक पेपर मिल को बिहार से नहीं हटाना चाहिये, लेकिन साथ साथ मेरा विश्वास है कि जो बेकारी और बेरोजगारी की समस्यायें हैं वह बड़ी-बड़ी मिलों से हल नहीं हो सकती हैं। बिहार में हरी क्रांति के साथ-साथ जो छोटी छोटी मशीनें लगाई गई हैं जिनमें धान काटने की मशीनें और आटा चक्की वगैरह भी शामिल हैं, उन पर बिजली विभाग ने 90 रु० से ले कर के 300 रु० तक का सरचार्ज लगाया है, चाहे काम हो या न हो। इस सरचार्ज के लगाने से लोगों की कमर टूट गई है। लाखों लोग जो इन कामों में लगे हुए हैं वे बेकार हो रहे हैं क्योंकि बिजली के रेट बढ़ जाने से वे

ठीक नहीं चल रही हैं । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो इन छोटी-छोटी मिलों पर बिजली का सरचार्ज है, जो जबर्दस्ती लगाया जा रहा है, चाहे काम हो या न हो, उसे हटा दिया जाये ।

हमारे माननीय मंत्री ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं । लेकिन मैं देख रहा हूं कि ग्रीन के बदले क्रांति का रंग लाल होता जा रहा है । इस का कारण यह है कि बिहार में पिछले मंत्रिमंडलों ने जो गैर मुजरवा आम और खास जमीनें है शिड्यूल्ड कास्ट्स और पिछड़े वर्गों के लोगों में बांटने की बात कही थी । लेकिन वह काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है । इस से बिहार में एक तरह का आन्दोलन खड़ा हो रहा है । आज गैर मुजरवा जमीनों को लेने के लिये ग्रुप के ग्रुप लोग किसी खास पार्टी के नेतृत्व में आते हैं और खूनखराबी करते हैं । इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा ऐसी भूमि का जो पड़ती पड़ी है बटवारा जल्दी से जल्दी आरम्भ कर दें ।

बिहार में लाख का उद्योग हजारीबाग और रांची में काफी था । किन्तु अब लाख की डिमान्ड बहुत कम हो गई है और यह उद्योग एक तरह से मृतप्राय होता जा रहा है । उसे पुनर्जीवित करने की बड़ी आवश्यकता है । इस पर लाखों लोगों की जीविका निर्भर करती है । इस लिये लाख के उद्योग को और लाख के उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार कुछ ठोस कदम उठाये ।

इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, हरी क्रान्ति की चर्चा बराबर की जाती है जिसमें कृत्रिम खादों का काफी योगदान है लेकिन सिन्दरी फर्टिलाइजर के एक विशिष्ट अधिकारी ने कहा है कि वास्तव में फर्टिलाइजर क्या करे जब हमारे यहां पानी ही नहीं है । पानी की बिहार में बड़ी कमी है । पानी के लिये बिजली के ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में बिजली का कनेक्शन देने की बात तय होने के महीनों नहीं वर्षों बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता । इस लिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वे जहां पर पम्प लग चुके हैं और बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, वहां उन को तुरन्त देने का प्रबन्ध करावें ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैंने सदन में सवाल किया था और प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखा था कि उत्तर बिहार और खास कर मधुबनी को जहां फसल बरबाद हो गई है ड्राउट की वजह से, फैमिन स्ट्रिकन एरिया घोषित किया जाए । आप अगर समझते हैं कि वहां अकाल की स्थिति नहीं है तो कम से कम डिफिसिट एरिया मधुबनी को आप घोषित करें । मैंने सवाल किया था जिस के जवाब में कहा गया कि बिहार गवर्नमेंट से स्टेटमेंट मांगा जा रहा है । प्रधान मंत्री का जवाब आया है कि आप की चिट्ठी मिल गई है । इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि उसको डिफिसिट एरिया तुरंत घोषित किया जाए । मैं चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक एक वक्तव्य आए और एलान भी आए । वहां हालत बहुत खराब है ।

उद्योगों को ले कर बताया गया है कि अशोक पेपर मिल वहीं रहनी चाहिये, उसको असम नहीं जाना चाहिये । मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन उत्तर बिहार में आम और लीची बहुत होती है । उसका वह भंडार है । वहां एक कैनिंग फैक्ट्री लगनी चाहिये । फलों को डिब्बों में बन्द करने का कारखाना वहां चल सकता है । सरकार उसकी ओर ध्यान दे । उत्तर बिहार में मधुबनी में या मुजफ्फरपुर में वह कैनिंग फैक्ट्री लग सकती है ।

मधुबनी में आर० के० कालेज 1940 से है । उसके बाद जो कालेज बने थे उनको तो बिहार यूनिवर्स्टी ने कंस्टिट्युएंट कालेज बना लिया है लेकिन आर० के० कालेज के दावे को नजर अंदाज कर दिया है । उसको अभी तक इगनोर वह कर रही है । उसको कंस्टिट्युएंट कालेज आज तक नहीं बनाया गया, यह बड़े दुख और शर्म की बात है । उसकी

[श्री शिवचन्द्र झा]

लैजिटिमेट डिमांड को इगनोर किया जाता रहा है। वह घाटे में चल रहा है। उसकी हालत दयनीय है। वह उस इलाके का एक प्रमुख कालेज है। मैं चाहता हूं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस पर गौर करें और आर० के० कालेज को बिहार यूनिवर्सिटी का एक कांस्टिट्युएंट कालेज बना दें।

जितना पैसा दिया जा रहा है, इसके बारे में मैं आश्वासन चाहता हूं कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, यह पैसा भ्रष्टाचार में चला नहीं जाएगा। मुझे शक है कि 75 परसेंट पैसा जो लिया जा रहा है, उसका दुरुपयोग होगा और 25 परसेंट का ही अच्छा इस्तेमाल होगा। हमें पच्चीस परसेंट के लिए स्वीकृति देनी चाहिये, 75 परसेंट के लिए नहीं। मैं आश्वासन चाहता हूं कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सारन जिले में ऊख उपजाने वाले किसान पंद्रह तारीख से हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पंद्रह रुपये क्विंटल ऊख की कीमत दी जाए और समय पर पैसों की अदायगी हो। उनकी यह मांग भी है कि जो उनका बकाया पड़ा हुआ है, वह उनको दिया जाए। साथ ही उनकी यह मांग भी है कि जो गाड़ियां ऊख की लद कर आती हैं, उनको छः घंटे से अधिक डिटेन न किया जाए। मैं चाहता हूं कि इस सब के बारे में सरकार सदन को बताये ताकि किसानों को आशा बंधे कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। वहां पर लोकप्रिय सरकार नहीं है, इस वास्ते इस सब की जिम्मेदारी आप पर ही आती है।

पटना यूनिवर्सिटी पर हम बहस कर चुके हैं। मैं पटना से आज ही लौटा हूं। पटना बी० एन० कालेज और साइंस कालेज जहां साइंस की पढ़ाई होती है, उसको मैंने देखा है। उसकी छत टूट-टूट कर छात्रों के सिर पर गिरती है। वहां पानी नहीं है एक्सपैरिमेंट करने के लिए। लैबोरेटरीज में वहां गैस नहीं है। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि जनता स्टोव पर वहां छात्र एक्सपैरिमेंट कर रहे हैं। साइंस कालेज भी बहुत पुराना कालेज है। प्रतिष्ठा रही है, उनकी। जितना भी इक्विप-मेंट है, यंत्र हैं, तमाम 1927 में खरीदे गए थे, आज 1969 है। आप यूनिवर्स्टी को अपने कब्जे में तुरन्त लें। साथ ही फौरन साइंस कालेज के लिए, बी० एन० कालेज के लिए, वहां लैबोरेटरीज़ को आधुनिक बनाने के लिए आप मदद दें, उनको आप विशेष आर्थिक सहायता दें।

पटना वहां की राजधानी है। वहां बहुत सी कालोनीज सरकार ने बनाई हैं। तमाम जगह गोल माल हुआ है। रुपये लोगों ने खाये हैं। पटना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भ्रष्टाचार का अड्डा है। इन तमाम बातों की आप इनक्वायरी करें ताकि वहां लोगों को मालूम हो कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं।

पटना शहर में शास्त्री नगर है। वहां गवर्नमेंट एम्प्लायीज़ रहते हैं। हज़ारों की तादाद में रहते हैं। उनके बच्चों के लिए वहां कोई स्कूल नहीं है। लोग चाहते हैं कि सरकार के जो खाली क्वार्टर पड़े हैं, उन में हाई स्कूल चलाने की सरकार इजाजत दे। वे अपने पैसे से उसको चलायेंगे। मैं चाहता हूं कि उसकी स्वीकृति आप दे दें। उस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये ताकि सरकारी कर्मचारियों का असन्तोष दूर हो और उनके बाल बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : I want to draw the attention of the......

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before you speak, I want to say this. I try my best to accommodate every member. But so many of you want to speak. Can you convert this into another general debate?

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begu-sarai) : I spoke only as a Member from Bihar.

SHRI RANJEET SINGH: I want to speak on behalf of the Jan Sangh. My hon. friend has spoken as a Bihari only.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members may kindly listen to me. We have already had a detailed discussion on the Demands but because some Members wanted to raise some points, I had allowed them just two or three minutes. Hon. Members may kindly co-operate with me. Let us not convert it into another full-fledged debate.

SHRI JYOTIRMOY BASU: I would only refer to the serious situation that prevails in Jharia and Dhanbad districts, and point out how the coal-mine-owners have taken the law into their own hands in order to avoid the implementation of the wage board award. They are beating up people. They have imported five hundred goondas in the Jharia coalfield area. The management has dared to make a sudden attack on the workers and engaged some 500 goondas in covinance with the police to get rid of the old permanent workers because they have been pressing them to have correct and quick implementation of the coal wage board award and the management is also trying to arrange a come-back of the goondas in the colliery as employees to subvert their working. One of my party union leaders was ruthlessly slaughtered in the presence of all in the Madhubani colliery. We would like Government to take serious steps against this hooliganism, and we would also like to know what Government are going to do in this matter.

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : On the electricity rate which is very much on the increase........

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is becoming a full-fledged debate once again.

SHRI HIMATSINGKA: I would take just half a minute. The electricity rate has been so much raised that it cannot be used. as a matter of fact. Irrigation becomes difficult with the increased electricity rates...

MR DEPUTY-SPEAKER: I think the hon. Member has understood his point. Now, the hon. Minister.

SHRI P. C. SETHI : We would have been very happy if there would have been a popular government in Bihar and the points which are agitating the minds of hon. Members here would have been agitated by the local MLAs in the assembly. But one good feature of the whole episode is that on account of this situation, hon. Members have got an opportunity to represent the various points of view and give very valuable suggestions. With regard to the Ganga basin where floods are occurring and erosion is taking place, I am not in a position to give an assurance, but I would only say that I would pass on information to the Government there for their consideration.

श्री कामेश्वर सिंह : मैं क्या कर सकता हूं । आप बिहार गवनमेंट को लिखें कि वह पंद्रह परसट खर्चा मीट करे ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने कहा है कि भेजूंगा । मैंने यह नहीं कहा कि आप भेजें । मैंने कहा है कि मै भेजूंगा ।

I shall write to them seriously. A point was made about the yield per acre of jute by Shri Bhogendra Jha. I am told that this has already been included in the Fourth Plan and this would soon receive their attention.

A point was made about the lac industry in the Bihar area. This scheme is already going on there since the Second Plan and it will be continued in the Fourth Plan period.

Shri Shiva Chandra Jha had made a reference about the canning industry in Bihar. So far as the canning industry is concerned, according to my information, there are already four processing plants for processing mangoes, leechis, papayas etc. in the districts of Muzaffarpur, Darbhanga and Purnea in North Bihar.

श्री शिवचन्द्र झा : प्रासमिग इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है । लेकिन मैं ने कैनिग इंडस्ट्री शुरू करने के बारे में कहा है । मैंने यह भी सुझाव दिया है कि मधुबनी को डेफ़िसिट एरिया घोषित कर दिया जाये ।

SHRI P. C. SETHI: I take note of the suggestions made by the hon. Member.

[Shri P. C. Seth

Shri Yogendra Sharma, shri Ramavatar Shastri and Shri Jyotirmoy Basu also made certain representations here, and I take cognizance or note of those references, and I would pass them on to the Bihar Government for their consideration.

SHRI YOGENDRA SHARMA: Regarding the sugarcane price, I understand that the Bihar Government have recommended to the Central Government here that the price should be Rs. 9 per quintal, whereas the peasants are getting only Rs. 7·27 now. If the Central Government have received this recommendation from Bihar Government, may I know whether they will sympathetically consider that?

SHRI P. C. SETHI : This must be with the Food and Agriculture Ministry and I shall check up.

SHRI RANGA (Srikakulam) I just want to say a few words. This budget or Appropriation Bill, if only there had been a legislature there in Bihar, would have been debated upon for nearly one month. But what is the time that we are able to give to this? I find that you had been pleased, in fact, to warn hon. Members of our party that they would be able to get only one minute. In regard to others also, you said that the total time was only one hour. Is that fair to Bihar? Is that a democratic way of dealing with Bihar?

SHRI RAGHU RAMAIAH: Time has been allocated by the Business Advisory Committee.

SHRI P.C. SETHI: This has been discussed fully before.

SHRI RANGA: I am not finding fault with anybody. I am only finding fault with the fate of Bihar and democracy.

SHRI YOGENDRA SHARMA: We support Shri Ranga at least in this matter. Bihar should have been given more time.

SHRI RANGA: I am not finding fault with anybody here. The point is this. There could have been a full-fledged debate for over a month in the usual manner in Bihar if only that Legislative Assembly had been allowed and had been helped and aided to function. But why has that not happened? It is not because of the unwillingness of the legislators there to get together and form a government............

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the hon. Member's point has been understood by the hon. Minister..........

SHRI RANGA: Let me be heard; I am the leader of my party........

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am only seeking his co-operation.

SHRI RANGA: That is why I have myself stood up. Otherwise, one of my party members was to have spoken.

The legislators were willing to form themselves into a coalition, and one of their own leader, Shri Harihar Singh, I think, agreed to get together and have a majority..

SHRI YOGENDRA SHARMA: He has absolutely no chance.

SHRI RANGA:....and form a Ministry with the co-operation of so many of the other parties including the party of my hon. friend......

SHRI YOGENDRA SHARMA: No.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: No; no. Not with our party.

SHRI RANGA: The Deputy-Speaker is worried so much about time, but my hon. friend is worried about something else.

My point is only this. If only those Congresss gentlemen who had been willing to co-operate with each other and who have now split in twine there in Bihar could have accepted the idea of coalition, then both of them could have agreed to co-operate with the other democratic political parties and formed a coalition Ministry and in that way afforded and given a good enough and decent enough chance to the Bihar Legislative Assembly to discuss this budget, and present the needs and grievances of the people there during the discussion in regard to each one of these Demands. But that opportunity has been lost for Bihar. Why? It is because of the ruling party's cussedness and revengeful spirit as against their own group, the other group namely the organisational group; if only the organisational group and so-called ruling group, both belonging to the Congress could have come into power with the help of the two bullocks, if only they had decided to play fair with democracy and play fair with Bihar,

there could have been a better discussion and a better consideration on the budget and the Appropriation Bill.

Therefore, I charge them for having failed Indian democracy. I charge them for having betrayed the people of Bihar and I advise them even now at this late hour to agree to co-operate with the other group of their own Congressmen as well as the other demratic parties in Bihar and help them to form themselves into a coalition Ministry and affored the people a good enough legislature and also a good enough Government for the people of Bihar.

SHRI YOGENDRA SHARMA: Has Prof. Ranga assumed the leadership of both the factions of Congress in Bihar?

SHRI RANGA: I can give them advice.

SHRI P. C. SETHI: I am thankful to Achargya Rangaji and I have nothing more to say except that coalitions cannot be formed unless there is a likeminded approach about the problems and principles if Acharya Rangaji's recommendation is to be followed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clauses 2, 3 the Schedule, clause 1, the enacting formula and the title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3, the schedule, clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

SHRI P.C. SETHI: I move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed.

The motion was adopted.

14.23 hrs.

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTFR IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK) : I beg to move that the Bill further to amend the Indian Tariff Act, 1934, be taken into consideration.

Before the hon Members of this House participate and express their views over this Bill, I would like to say a few words about the objects and reasons why this Bill is being introduced here for consideration. This Bill seeks to amend the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 in order to give effect to the Government's decision on the recommendations of the Tariff Commission relating to the sericulture industry. Hon. Members know that the protection to this industry is going to expire on 31st December 1969. Copies of the Tariff Commission's report on the sericulture industry and the Government's resolution issued thereon have already been laid on the Table of the House. A gist of the Tariff Commission's report and the recommendations of the Sericulture Industry have been circulated to the Members. Imports of raw silk into this county........

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): On a point of order, Sir, I want this matter to be decided once for all...As per Art. 117 of the Constitution a Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a)to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President etc. etc. It must not be introduced or moved without the recommendation of the President. Here, this Bill is only recommended to be introduced. Where is the recommendation for moving?

Two alternate recommendations are necessary—introduce or move. Here he has got permission for introduction. Please see page 3:

"The President having been informed of the subject matter of the Indian Tariff (Amendment) Bill, 1969, recommends under art. 117 (1) of the Constitution of India, the introduction of the Bill in the November-December, 1969, session of the Lok Sabha".